भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

25 नवंबर, 2014

दिवालिया आत्मसमर्पण नीति के विरोध में

केंद्र व छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की दिवालिया आत्मसमर्पण नीति का हमारी पार्टी कड़ा विरोध करती है एवं जनता, जनवादियों व मानवधिकार संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने व घृणा करने की अपील करती है।

संघर्ष इलाकों में तैनात विभिन्न सशस्त्र बलों को सरकारें इस आत्मसमर्पण नीति के तहत एवं मुखबिरी के नाम पर दसियों करोड़ रूपयों का अन–ऑडिटबल फंड़ मंजूर करके बलों का आपराधीकरण कर रही है। क्रांतिकारियों के सिरों पर ईनाम घोषित करके न केवल समाज में बल्कि सशस्त्र बलों में लंपट संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईनाम व प्रमोशन के के चक्कर में क्रूर पुलिस अधिकारियों के द्वारा लगातार गांवों पर हमलें करके आम आदिवासी, गैर आदिवासी किसानों, युवाओं को गिरफ्तार करके उन्हें ईनामी माओवादी घोषित किया जा रहा है। कइयों को डरा धमकाकर, दबाव डालकर आत्मसमर्पण का नाटक रचा जा रहा है। विस्थापन विरोधी एवं थाना–कैम्प विरोधी आन्दोलनकारियों व जनपक्षधर सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके भी ईनामी नक्सली करार दिया जा रहा है। यहां यह गौर करने वाली बात है कि भाकपा व कांग्रेस पार्टियां भी इसके विरोध में बयान जारी कर चुकी हैं।

प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आये दिन माओवादियों के आत्मसमर्पण व गिरफ्तारी से संबंधित पुलिसिया दुष्प्रचार हमारी पार्टी को बदनाम करने एवं जनता हमारी पार्टी व पीएलजीए की कतारों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने का हिस्सा है। यह हमारी पार्टी, पीएलजीए, जनसंगठनों व जनताना सरकारों को खत्म करने के लिए सरकारों के द्वारा अमल में लायी जा रही विश्वासघाती कम तीव्रता वाली युद्ध नीति (एलआइसी) के तहत जारी चौतरफा हमले का हिस्सा है। हालांकि यह सच है कि हमारी कतारों के कुछ कमजोर कैडर सरकारों की आत्म समर्पण नीति से आकर्षित होकर पुलिस की शरण में जा रहे हैं। ऐसे लोगों से क्रांतिकारी जनता नफरत करती है। ऐसे लोग जनता व पार्टी के साथ गद्दरी करके जब पुलिस के साथ मिलकर गांवों में आते हैं तो लोग उन्हें पीट रहे हैं, उनके मूंह पर थूक रहे हैं, खरी–खोटी सुना रहे हैं। ऐसे ढ़ेरों उदाहरण हैं। आत्मसमर्पित भूतपूर्व माड़ डीवीसी सदस्य नवीन जब पुलिस के साथ गांवों पर हमले करने आया तो हजारों लोगों ने उसे गिरफ्तार करने, जान से मारने की मांग करते हुए धनोरा (नारायणपुर) थाने के सामने प्रदर्शन किया।

विभिन्न कारणें से पार्टी छोड़कर साधारण जीवनयापन करने वालों जिनमें शादी–शुदा, बाल–बच्चेदार भी हैं, को भी गिरफ्तार करके ईनामी माओवादी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल आत्मसमर्पण व मुखबिरी के लिए आंबटित बजट का बड़े पुलिस अधिकारियों के बीच बंदरबांट हो रहा है। मिसाल के तौर पर बारसूर इलाके के चिउरबाई गांव की सीता की ही कहानी लें। वह हमारी पीएलजीए की बटालियन–2 की साधारण सदस्या थी । जून, 2014 में वह पार्टी छोड़कर गयी थी और दूसरे गांव में साधारण जीवन बिता रही थी। उसके बाप के जरिए उसका कोड़ेनार पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करवाया गया, पत्रकारों के सामने पेश किया गया, हमारी पार्टी के खिलाफ बयान जारी करवाया गया और उसे 8 लाख की ईनामी माओवादी घोषित करके उसके बाप को मात्र 5 हजार रूपये देकर भेज दिया गया था। ऐसे सैकड़ो उदाहरण हैं।

गांवों पर हमलों के दौरन 15 से लेकर 45 साल के बीच की उम्र के लोगों को पकड़कर ले जाना, मुखबिर, एसपीओ बनने दबाव डालना, आत्मसमर्पण का नाटक दिखाना, मुखबिर बनने से इनकर करने वालों की गिरफ्तारी दिखाकर फर्जी मामलें बनाकर जेलों में डालना या झूठी मूठभेड़ों में निर्मम हत्या करना, छग सरकार के दिशा निर्देशन में पुलिस के द्वारा जारी जन दमन नीति का यह एक अहम हिस्सा है। बस्तर रेंज का आईजी कल्लूरी शिवराम प्रसाद संभाग में इस नाटक का निर्देशक है। हमारी पार्टी संघर्ष इलाकों की जनता, जनसंगठनों, क्रांतिकारी जनताना सरकारों, मिलीशिया एवं पार्टी व पीएलजीए की तमाम कतारों का आव्हान करती है कि आत्मसमर्पण से नफरत करें, आस्तित्व, आत्म सम्मान, असली आजादी, असली विकास के लिए आखिरी दम तक आंदोलन में डटे रहने का संकल्प लें और सरकारों की दिवालिया आत्म समर्पण नीति को दफना दें।

प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं से हमारी पार्टी अपील करती है कि वे संघर्ष इलाकों का दौरा करें एवं दिवालिया आत्मसमर्पण नीति का भंडाफोड़ करें। मानवाधिकार संगठनों से अपील करती है कि वे सरकारों के द्वारा अपनायी जा रही गैर–संवैधानिक, आपराधिक एवं षड़यंत्रकारी तौर–तरीकों का खुलकर विरोध करें।

गुड्सा उसेंडी

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)